भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1803

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है ।

19 अग्रहायण, 1947 (शक)

ज़ोहो के साथ समझौता

1803 श्री. यूसुफ पठान:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2023 में मंत्रालय और विभागीय खातों सहित केन्द्र सरकार की ईमेल सेवाओं को ज़ोहो कॉर्पोरेशन के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने के लिए एक समझौता किया था और यदि हां, तो निविदा प्रक्रिया, बोलियों के तुलनात्मक मूल्यांकन और अब तक स्थानांतरित किए गए प्रयोक्ता खातों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्थानांतरित करने से पहले सीईआरटी-इन और एनआईसी समेत कितने ऑडिट और सुरक्षा-अनुपालन आकलन पूरे किए गए; और

(ग) क्या सरकार का विचार वेंडर कॉन्ट्रैक्ट में होस्टिंग लोकेशन, डेटा सॉवरेनिटी प्रोविज़न और सर्विस कंटिन्यूटी सेफ़गार्ड का खुलासा करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों के लिए एक मजबूत, संप्रभु और सुरक्षित आधिकारिक ई-मेल प्रणाली के महत्व को स्वीकार करती है। तदनुसार, सरकार अधिदेशित करती है कि आधिकारिक संचार के लिए केवल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-मेल सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।

इसे सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एनआईसी के माध्यम से एक मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) - मैसर्स जोहो का चयन किया है, जो सभी सरकारी उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने में सक्षम क्लाउड-आधारित ईमेल समाधान है।

यह मॉडल पेशेवर उन्नयन, मौजूदा खातों का निर्बाध प्रवासन और वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे आधुनिक कार्यालय उत्पादकता उपकरणों का एकीकरण सुनिश्चित करता है।

यह सरकारी कर्मचारियों को भारत में विकसित एक एकीकृत सहयोग स्वीट तक पहुंच प्रदान करता है। अब तक स्थानांतरित किए गए मंत्रालयों और विभागों के उपयोगकर्ता खातों की संख्या लगभग 12.68 लाख है।

यह चयन सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं और सरकारी उपयोगकर्ताओं के नामित समूहों के साथ प्रूफ ऑफ़ कांसेप्ट (पीओसी) शामिल था।

यह परियोजना "मेक इन इंडिया" अनुपालन पर जोर देती है और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार अनुबंध के तहत उत्पन्न सभी डेटा और बौद्धिक संपदा का पूर्ण स्वामित्व बनाए रखे।

नए जोहो प्लेटफॉर्म पर ईमेल सेवा के लाइव होने के बाद, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के उपयोगकर्ताओं से ऑनलाइन प्रतिक्रिया एकत्र की गई।

सुरक्षित माइग्रेशन और डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सुरक्षा मूल्यांकन किए गए हैं:

- मई 2024 में मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी), एमईआईटीवाई द्वारा व्यापक सुरक्षा लेखापरीक्षा
- प्रगट संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), एमईआईटीवाई द्वारा अगस्त 2025 में दूसरी पूर्ण सुरक्षा लेखापरीक्षा

सेवा प्रदाता के साथ अनुबंध डेटा संप्रभुता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करता है। प्राथमिक और आपदा क्षतिपूर्ति डेटा केंद्रों सहित क्लाउड-आधारित समाधान भौतिक रूप से भारत के भीतर स्थित हैं और किसी भी डेटा को देश के बाहर साझा नहीं किया या दोहराया नहीं जा सकता है।

सेवा प्रदाता - मैसर्स जोहो, भारतीय कानूनों और अधिकार क्षेत्र के अधीन एक पंजीकृत भारतीय इकाई है।

*****